सी० आइ० टी० यू० की कार्य समिति ने देशव्यापी संयुक्त संघर्ष चलाने का आह्वान किया

विमल रणदिवे नगर, जयपुर में 13 से 16 नवंबर, 1999

सी० आइ० टी० यू० की अखिल भारतीय कार्य समिति ने, तीन दिन चले अपने विचार-विमर्श के बाद मजदूर वर्ग का आह्वान किया है कि देशव्यापी एकजुट कार्रवाई की तैयारी करे ताकि वाजपेयी सरकार की जन विरोधी तथा राष्ट्रविरोधी नीतियों को रोका जा सके जिन्होंने अर्थव्यवस्था तथा नागरिक समाज में गिरावट, उन्हें अस्तव्यस्त करने तथा उनके सर्वनाश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सी० आइ० टी० यू० कार्य समिति ने सभी संबद्ध यूनियनों का आह्वान किया है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर एक जबर्दस्त संघर्ष के लिए तैयारी करें।

सी० आइ० टी० यू० कार्य समिति की बैठक से पहले, 13 नवंबर जयपुर शहर में एक विशाल रैली हुई, जिसमें हजारों की संख्या में मजदूरों ने हिस्सा लिया। रैली को सी० आइ० टी० यू० के अखिल भारतीय अध्यक्ष ई० बालानंदन तथा महासचिव एम० के० पंधे, सी० आइ० टी० यू० के सचिव चित्तब्रत मजूमदार, सी० आइ० टी० यू० के राजस्थान राज्य समिति के अध्यक्ष हेतराम बेनीवाल तथा महासचिव रवींद्र शुक्ला और राज्य किसान सभा उपाध्यक्ष व विधायक, आमरा राम ने संबोधित किया। सी० आइ० टी० यू० के राज्य उपाध्यक्ष, कृष्णकांत वर्मा ने इस जनसभा की अध्यक्षता की।

संगठन का झंडा फहराए जाने तथा सी० आइ० टी० यू० के अखिल भारतीय अध्यक्ष ई० बालानंदन के अध्यक्षीय भाषण (देखें बाक्स पृष्ठ 5 पर) के साथ, 14 नवंबर को कार्य समिति की बैठक शुरू हुई।

महासचिव, एम० के० पंधे ने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए रेखांकित किया कि भाजपा के नेतृत्ववाले गठजोड़ के फिर से केंद्र में सत्ता में आ जाने के चलते, पूरे समाज के लिए किस तरह के नए खतरे पैदा हो गए हैं। सांप्रदायिक भाजपा के नेतृत्व में चौबीस पार्टियों के अवसरवादी गठजोड़ के केंद्र में सत्ता में आ जाना, अपने पीछे खतरनाक संकेतों को छुपाए हुए है। वास्तव में इसी गठजोड़ के 17 महीने के पिछले शासन में इस देश पर जिस तरह के सांप्रदायिक षड्यंत्र थोपे गए थे, उन्हें आगे बढ़ा दिया गया है। इस बार की चुनावी विजय से उत्साहित केसरिया पलटन ने अपने दांत तथा पंजे और चमकाने शुरू कर दिए हैं, जिसका सबूत पोप की भारत यात्रा के मौके पर मिल गया है। शिक्षा, प्रशासन तथा दूसरी तमाम संस्थाओं का केसरियाकरण करने की भाजपा के नेतृत्ववाली सरकार की नंगी मुहिम जोर-शोर से जारी है। इसमें देश के जनतांत्रिक ताने-बाने के लिए तथा मेहनतकश जनता की एकता के लिए भी खतरे के संकेत निहित हैं। पंधे ने जोर देकर कहा कि मजदूर वर्ग को, भाजपा के नेतृत्ववाली सरकार तथा संघ परिवार की ऐसी तमाम सांप्रदायिक व विघटनकारी साजिशों के खिलाफ, अपनी संगठित आवाज उठानी होगी।

अर्थ व्यवस्था में गिरावट

अपनी रिपोर्ट में एम० के पन्धे ने राष्ट्रीय परिस्थिति का भी संक्षिप्त ब्यौरा पेश किया। उन्होंने बताया कि किस तरह अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सर्वव्यापी गिरावट आ रही है। भाजपा के नेतृत्ववाली सरकार पिछले डेढ़ साल से उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की जिन नीतियों को जोर-शोर से लागू कर रही हे उनके चलते, गरीबी बढ़ रही है तथा और उग्र हो रही है। औद्योगिक विकास दर गिरी है, उद्योगों के बीमार होने तथा बंद होने के प्रकरण बढ़े हैं और रोजगार सृजन नकारात्मक हो गया है अर्थात् पहले से रोजगार में लगे लोग रोजगार से हाथ धो रहे हैं तथा बेरोजगारी और भी तेजी से बढ़ रही है। अनुमानों के अनुसार, 1999 के मार्च के महीने में समाप्त हुए एक वर्ष के दौरान ही, अकेले संगठित क्षेत्र में कुछ लाख रोजगारों का नुकसान हुआ है। असंगठित क्षेत्र में अर्द्ध-रोजगार तो आम बात ही हो गयी है।

विदेशी निवेश को आकर्षित करने के नाम पर जो विदेशी पूंजी को विभिन्न रूपों में जो नित नयी-नयी रियायतें दी गयीं हैं, उनके बावजूद बहुत ही कम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आए हैं। वास्तव में पिछले कुछ अर्से में इन निवेशों में भी गिरावट का ही रुझान देखने में आया है जबकि इस चक्कर में घरेलू उद्योगों को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया है और बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा भारतीय कंपनियों का अधिग्रहण सुगम बना दिया गया है। तथ्यगत स्थिति यह है कि विदेशी कंपनियों का शुद्ध रोजगार निर्माण व्यावहारिक मानों में नकारात्मक ही रहा है क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अधिगृहीत सभी कंपनियों द्वारा अधिगृहीत सभी कंपनियों में रोजगार में भारी कमी आयी है।

उदारीकरण के पैरोकारों के सारे दावों के बावजूद और विश्व व्यापार संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के आकाओं को खुश करने के लिए देश की अर्थव्यवस्था के दरवाजे चौपट खोले जाने के बावजूद, निर्यात के मोर्चे पर भारत लगातार घाटे में ही जा रहा है और पिछले वर्ष तो निर्यातों में बढ़ोतरी के बजाय शुद्ध गिरावट दर्ज हुई थी। भाजपा के नेतृत्ववाली सरकार ने, कांग्रेस की मिलीभगत से बारहवीं लोकसभा में, जल्दबाजी में पेटेंट कानून में संशोधन का जो कानून पारित कराया था, आने वाले वर्षों में उसके सर्वनाशी नतीजे सामने आने वाले हैं। विकसित देशों के ग्रुप, जी-7 द्वारा विश्व व्यापार संगठन के सिएटल में होने जा रहे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में, विकासशील देशों पर अपना शिकंजा ओर कसने की तैयारियां की जा रही हैं। भारत को, हर कीमत पर इन चालों का विरोध करना होगा।

दूसरी पीढ़ी के सुधार

कामरेड पंधे ने अपनी रिपोर्ट में वांशिगटन में बैठे अपने आकाओं को खुश करने की भाजपा के नेतृत्वाली सरकार की बदहवास कोशिशों

ने चुनाव प्रचार के दौरान के अपने अनुभवों के बारे में बताया और यह भी बताया कि किस प्रकार भाजपा के नेतृत्व वाले खेमे और कांग्रेस पार्टी, दोनों द्वारा उदारीकरण की नीतियों की तथाकथित अपविवर्तनीयता साबित करने की तिकड़में की जा रही थीं और इस संबंध में दावे करने में होड़ की जा रही थी ताकि पूंजीवादी लाबी की सहायता व समर्थन हासिल किए जा सकें। इन हालात का तकाजा है कि मजदूर वर्ग तथा ट्रेड यूनियन आंदोलन द्वारा उदारीकरण की नीतियों के विकल्प की नीतियां जनता के सामने पेश की जाएं और मौजूदा सरकार की प्रतिगामी व जनविरोधी नीतियों के खिलाफ, देश भर में विराट प्रतिरोध आंदोलन का निर्माण किया जाए, जैसाकि चर्चा के दौरान विभिन्न वक्ताओं ने रेखांकित किया।

बहस का समाहार करते हुए सी० आइ० टी० यू० अध्यक्ष ई० बालानंदन ने आने वाले दिनों में एकजुट संघर्ष का निर्माण करनेकी अपरिहार्यता पर जोर दिया और सी० आइ० टी० यू० से संबद्ध संगठनों का आह्वान किया कि इस चुनौती का सामना करने के लिए जरूरी सांगठनिक तैयारियां करें। एम० के० पंधे ने बहस का जवाब दिया। ई० बालानंदन की अपुपस्थिति में, उपाध्यक्ष समर मुखर्जी ने समापन भाषण किया क्योंकि कामरेड बालानंदन एक और महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के लिए पहले ही चले गये थे। निम्नलिखित फौरी कामों को पूरी गंभीरता के साथ हाथ में लेने के आह्वान के साथ सी० आइ० टी० यू० कार्य समिति का समापन हुआ।

प्रतिरोधी संघर्ष

कार्य समिति ने सर्वसम्मति से यह निष्कर्ष निकाला कि दूसरी पीढ़ी के सुधार के नाम पर, निजीकरण तथा अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए सरकार द्वारा दिखाई जा रही बदहवास जल्दबाजी और मजदूरों के अधिकारों पर हमलों के खिलाफ, एक देशव्यापी आंदोलन का निर्माण करना आज का सबसे जरूरी काम है और सी० आइ० टी० यू० को इसके लिए चौरतफा पहल करनी चाहिए। भाजपा के नेतृत्ववाली सरकार को निजीकरण की अंधी मुहिम तथा उसके अन्य नीति संबंधी कदमों के खतरनाक निहितार्थों के संबंध में और श्रम अधिकारों पर हमला की उसकी बेशर्म साजिश और सांप्रदायिक व फूटपरस्त नीतियों के संबंध में आज मजदूरों तथा जनता को जागरूक करने के लिए सभी सी० आइ० टी० यू० इकाइयों को सघन अभियान छेड़ना चाहिए। उन्हें आने वाली कठिन लड़ाई के लिए जरूरी सांगठनिक तैयारियां भी करनी चाहिए।

कार्यसमिति ने इस पर संतोष प्रकट किया कि संबद्धताओं से ऊपर उठकर, सभी मजदूरों व ट्रेड यूनियनों ने सरकार की प्रतिगामी आर्थिक नीतियों पर और ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमलों पर, विरोध प्रकट किया कि कार्य समिति ने मजदूर वर्ग का आह्वान किया है कि इस विरोध को, एक व्यापक प्रतिरोध संघर्ष के रूप में देश भर में फैला दे। कार्य समिति ने ट्रेड यूनियनों की आयोजन समिति के निर्णय की पुष्टि करते संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन, 29 नवंबर को "राष्ट्रीय विरोध दिवस" मनाने का आह्वान किया और इस मौके पर सभी राज्यों की राजधानियों में तथा औद्योगिक केंद्रों में विशाल प्रदर्शनों के आयोजन की अपील की। इसी रोज, बैंक व बीमा कर्मियों के साथ, संसद पर मजदूरों का एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा।

कार्य समिति ने बैंकिंग व बीमा क्षेत्र की ट्रेड यूनियनों तथा अफसरों की एसोसिएशनों के इस संयुक्त निर्णय का स्वागत किया है कि बीमा नियमन प्राधिकरण विधेयक जिस रोज संसद में विचार के लिए आएगा, उसके अगले ही रोज देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। कार्य समिति ने समूचे ट्रेड यूनियन आंदोलन का और खासतौर पर सी० आइ० टी० यू० से संबद्ध यूनियनों का आह्वान किया है कि उक्त हड़ताल के दिन, वित्तीय क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ एकजुटता प्रकट करते हुए जोरदार विरोध कार्रवाइयों का आयोजन करें ।

कार्य समिति ने यह भी तय पाया कि सार्वजनिक क्षेत्र की यूनियनों की कमेटी (सी० पी० एस० टी० यू०) के साथ मिलकर, सार्वजनिक क्षेत्रवासियों के एकजुट संघर्ष के निर्माण के लिए पहल की जाए जो, चरणबद्ध अभियान व आंदोलन से होते हुए, आने वाले महीनों में देशव्यापी हड़ताल में अपने उत्कर्ष पर पहुंचे। कमेटी ने इस पर गौर किया कि कोयला, गोदी व बंदरगाह, परिवहन, सीमेंट, कपड़ा तथा बिजली क्षेत्रों में, सी० आइ० टी० यू० की यूनियनों द्वारा पहले ही एकजुट आंदोलन के

सी आइ टी यू के आगामी कार्यक्रम

सी० आइ० टी० यू० की कार्य समिति ने अनेक सांगठनिक कदमों का भी निर्णय लिया है, जिनमें से प्रमुख कदम इस प्रकार हैं:

० सन् 2000 की 18 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली में संगठन पर एक तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। सी० आइ० टी० यू० केंद्र द्वारा इस सिलसिले में एक प्रश्नावली पहले ही वितरित की जा चुकी है, जिसके उत्तर राज्य कमेटियों/फैडरेशनों द्वारा 15 जनवरी 2000 तक भेज दिए जाएंगे।

० सी० आइ० टी० यू० का आगामी महाधिवेशन, सन् 2000 में 27 से 31 दिसंबर तक आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में होगा।

० कामगार महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति का दो दिवसीय सम्मेलन अलग से आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन के स्थान तथा तिथियों का निर्णय बाद में किया जाएगा।

० सी० आइ० टी० यू० महा परिषद (जनरल काउंसिल) की अगली बैठक, सन् 2000 में अप्रैल के महीने में कोजीकोडे केरल में होगी।

निर्माण के लिए पहलें की जा रही हैं।

कार्य समिति ने तय पाया कि ट्रेड यूनियनों की आयोजन समिति में अपने सहयोगियों के साथ और अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व अन्य अखिल भारतीय फैडरेशनों के साथ भी परामर्श कर और विभिन्न क्षेत्रों में आंदोलनकारी पहलों के साथ तालमेल बैठाकर, सी० आइ० टी० यू० सरकार की सत्यानाशी राष्ट्रविरोधी नीतियों के खिलाफ तथा श्रम अधिकारों पर हमलों के खिलाफ और देश की अर्थव्यवस्था को ही बेचने की खतरनाक साजिश का प्रतिरोध करने के लिए, देशव्यापी हड़ताल समेत एक जबर्दस्त आंदोलन के निर्माण के लिए प्रयास करेगी।

सरकार की जन विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ इंटक तथा भारतीय मजदूर संघ (बी० एम० एस०) द्वारा भी विरोध की आवाज उठाए जाने पर सी० आइ० टी० यू० ने गौर किया और उनके नेतृत्व से सी० आइ० टी० यू० ने अपील की कि वे देशव्यापी एकजुट संघर्ष के लिए ट्रेड यूनियनों की आयोजन समिति की पहल में हिस्सा लें।

कार्य समिति ने देश भर में मजदूर वर्ग का आह्वान किया कि आर० एस० एस०, विहिप, बजरंग दल आदि सांप्रदायिक संगठनों की गतिविधियों के संबंध में और शिक्षा, प्रशासन तथा देश की दूसरी विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थाओं का सांप्रदायीकरण करने की भाजपा के नेतृत्ववाली सरकार की कोशिशों के खिलाफ, सतर्क रहें। सांप्रदायिक सद्भाव की हर कीमत पर रक्षा करनी होगी। इसके बिना देश व मेहनतकश जनता के हितों की रक्षा करने के लिए, जनतांत्रिक आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

कामकाजी महिलाओं के मोर्चे पर

कार्य समिति ने रेखांकित किया कि सी० आइ० टी० यू० में कामकाजी महिलाओं की संख्या उनकी सकल सदस्य संख्या और उसके साथ साथ सी० आइ० टी० यू० की सदस्य संख्या की प्रतिशतता की दृष्टि से भी कुछ वृद्धि हुई है। किन्तु इसके साथ ही यह भी देखा गया कि इन महिलाओं की विशाल श्रेणियां विचारधारा की दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं और उनके द्वारा अनेक राज्यों में भाजपा तथा उसके सहयोगी दलों के पक्ष में मतदान किया गया है। अत: निर्णय लिया गया कि सी० आइ० टी० यू० की राज्य समितियां प्रसूति लाभ, समान कार्य के लिये समान वेतन, यौन उत्पीड़न के विरोध में कानून बनाने जैसे विषयों को लेकर राज्यव्यापी अभियान चलाएं और इन अधिकारों के माध्यम से उन्हें गोलबंद तथा संगठन में सक्रिय करें। यह निर्णय लिया गया कि सी० आइ० टी० यू० की सभी राज्य समितियां कामकाजी महिलाओं के मध्य अपने कार्य की तत्काल समीक्षा करें तथा भावी कार्यों की योजना बनाएं और इसके लिये समुचित काडर उपलब्ध कराएं।

उड़ीसा की आपदा

इस सबके अलावा कार्य समिति जहां उड़ीसा में सुपर-साइक्लोन अथवा चक्रवाती तूफान में हुई भारी तबाही तथा जनहानि पर गहरी चिंता व दु:ख का इजहार किया वहीं मजदूर वर्ग तथा खासतौर पर सी० आइ० टी० यू० यूनियनों का आह्वान किया कि इस मौके पर बढ़ चढ़ कर आगे आएं और समुद्री तूफान की तबाही की चपेट में आए लोगों के लिए यथासामर्थ्य मदद दें। कार्य समिति ने इस पर गौर किया कि सी० आइ० टी० यू० की अनेक राज्य कमेटियों तथा यूनियनों ने पहले ही समुद्री तूफान पीड़ितों की मदद के लिए धन तथा सामग्री एकत्रित करने के लिए पहल की है। सी० आइ० टी० यू० समिति ने अपने सम्बद्ध श्रमिक संगठनों का आह्वान किया है कि वे राहत सामग्री इकट्ठी करने के मामले में दोगुणा शक्ति के साथ प्रयास करें। इसके साथ ही उसने भारत सरकार से आग्रह किया कि उड़ीसा की इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और राहत, पुनर्वास व पुनर्निर्माण के लिए सभी संभव सहायता मुहैया करायी जाए।

सी० आइ० टी० यू० कार्य समिति ने अलग से एक प्रस्ताव स्वीकार कर, त्रिपुरा में एक उग्रवादी संगठन द्वारा 17 निर्दोष लोगों की नृशंस हत्याओं की भर्त्सना की और केंद्र सरकार से आग्रह किया कि त्रिपुरा में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ायी जाए ताकि आतंकवादियों की चालों का मुकाबला किया जा सके। इसके साथ ही काय्र समिति ने त्रिपुरा की वाम मोर्चा सरकार के विरुद्ध चलाए जा रहे निंदा अभियान को परास्त करने का आह्वान भी किया है।